RAJYA SABHA

Friday, the 3rd August, 1984/12 *Sravana* 1906 *(Saka)*

The House met at eleven of the clock, Mr. Chairman in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

MR. CHAIRMAN: Question No. 181. Shri Ram Chandra Vikal,

SHRI RAM CHANDRA VIKAL: Question No. 181.

Bonus on the Production of Wheat to Farmers

*181. SHRl RAM CHANDRA VIKAL:f

SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK:

Will the Minister of AGRICULTURE he pleased to state;

(a) whether the Central Government have received any representation from the farmers of Punjab and Haryana for the payment of bonus on production of wheat;

(b) whether it is a fact that the farmers of the above "two States have demanded upward revision of paddy prices to the level recommended by the Agricultural Prices Commission; and

(c) whether their demands have been considered by the Central Government; if so, with what results?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) A proposal was received from the Government of Punjab for the payment of bonus on the procurement of wheat.

(b) and (c) There have heen representations from various quarters about upward revision of procurement prices of paddy. The Government of India, after consulting the State Government and concerned authorities and keeping in view the read **to** provide sufficient incentive to the farmers as also the interests of the consumers and overall economic implications, fixed the procurement price for varieties of paddy in the "common" group at the level recommended by the Agricultural Prices Commission for the 1984-85 marketing season. This price is higher than the procurement price for the corresponding group of paddy fixed for the 1983-84 marketing season by Rs. 5.00 per quintal.

fThe question was actually askea on the floor of the House by Shri Ram Chandra Vikal.

श्री राम चन्द्र विकल : मैं कृषि मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पंजाब सरकार की तरफ से जो मांग आई है वह कब आई और क्या पंजाब के अलावा अन्य राज्यों की सरकारों ने किसानों के बोनस के बारे में कोई मांग की है और अगर की है तो सरकार की नीति बोनस देने के बारे में क्या है ?

श्री योगेन्द्र मकवाणा : डेट तो मेरे पास नहीं है कि कौन सी डेट में आई लेकिन . . .

श्री सभापति] : बोनस के बारे में ?

श्री योगेन्द्र मकवाणा : डेट नहीं है कि कौन-सी डेट पर आई लेकिन प्रोक्योरमेंट शुरू हुआ तभी इसकी मांग आई थी। दूसरे राज्यों से ऐसी कोई मांग नहीं है।

श्री राम चन्द्र विकल : मैं यह पूछ रहा हूं कि बोनस देने के बारे में क्या नीति है ? यह स्पष्ट नहीं हुआ

श्री सभापति : कुछ बताया नहीं ।

राव बीरेन्द्र सिंह : यह जो बोनस देने की बात है यह पंजाब गवर्नमेंट ने की

है । यह अगली फसल के लिए की है । अभी जो पैडी प्रोक्योरमेंट हो रहा है यह उसके लिए नहीं है । भारत सरकार ने सारे देश के लिए आगे के लिए जो कीमतें तय की हैं ये कीमतें तो हमने तय की हैं लेकिन उसके अलावा पंजाब सरकार ने अपने खजाने से तीन रुपये और फालतू देने की बात की है। यह पंजाब गवर्नमेंट का फैसला है हमारा नहीं

श्री सभापति : बोनस का ।

राव बीरेन्द्र सिंह : पैडी के ऊपर ।

श्री राम चन्द्र विकल : गेहूं के बारे में पहले पूछ रहा हूं, पैडी का दूसरा नम्बर है । यह जो मांग सरकार ने की, बोनस के बारे में यह कब की है और हरियाणा सरकार ने भी की है ।

श्री सभापति : तारीख नहीं है उनके पास ।

श्री राम चन्द्र विकल : इसके बारे में नीति क्या है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : नीति साफ है, बोनस देने के हक में हम नहीं हैं । जब गेहूं की पैदावार बहुत कम थी 76–77 तक, उस वक्त बोनस दिया जाता था, कहीं कहीं किसी स्टेट में जहां प्रोक्योरमेंट ज्यादा था और वह बोनस भी प्रोक्योरमेंट पर दिया जाता था, प्रोडक्शन पर नहीं जैसा आप सोच रहे हैं । इतने तख्मीने से ज्यादा जब प्रोक्योर होगा जैसे 2, 3 या 4 लाख टन से ऊपर या जो टारगेट किसी स्टेट का मुकर्रर किया हुआ है उससे ज्यादा वह सप्लाई करके दिखाएगा तो उस पर दिया जायेगा । उस टारगेट से बढ़कर जो प्रोक्योरमेंट होगा उसके ऊपर बोनस की तजवीज थी । वह दिया गया । लेकिन उसके बाद कहीं भी बोनस की कोई स्कीम हमने नहीं मानी; मंजूर नहीं की है और वैसे यह मामला फूड और सिविल सप्लाई मिनिस्टर से ताल्लुक रखता है, लेकिन मैं जवाब दे रहा हूं । यह महकमा एग्रीकल्चर के साथ है जो कीमतें हैं वे फूड डिपार्टमेंट के साथ हैं । फूड एंड सिविल सप्लाई अलग है ।

श्री सभापति : वे कहां हैं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : यहां नहीं हैं ।

श्री राम चन्द्र विकल : सभापति महोदय, मैं बहुत स्पष्ट चाहता हूं कृषि मंत्री जी से कि जो उन्होंने आधे रूप में तो माना कि जब पैदावार कम थी, तब हम बोनस देते थे किसान को प्रोत्साहन के लिए, तो क्या देश के किसानों के हित में और देश की पैदावार बढ़ाने के हित में यह पालिसी सही नहीं होगी कि हम पैदावार पर ही बोनस दें और किसान प्रोत्साहित होकर पैदावार बढ़ाते रहें ? अगर किसान पैदावार बढ़ाते रहेंगे, तो बोनस नहीं देंगे, कम होगी तो बोनस देंगे, यह देश के, किसान के और पैदावार के हक में नहीं है ।

तो इस नीति में परिवर्तन करके क्या वह हर हालत में किसान को बोनस देने पर विचार कर रहे हैं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : यह तो तजवीज है माननीय सदस्य की, जिसको हमने नोट कर लिया है । लेकिन पैदावार बढ़ाने के सिर्फ बोनस देने की बात से काम नहीं चलता, और बहुत से इन्सेंटिव्ज हैं, जो हम दे रहे हैं—कीमतें अच्छी मुकर्रर कर रहे हैं, जिससे किसान को फायदा होता है । सीधा फायदा तो किसान को दूसरे इन्सेंटिव से है—खाद ठीक वक्त पर मिले, उसकी कीमतें ठीक हों, जो बाजार में भाव मुकर्रर किया जाता है खरीद का

प्रक्योरमेंट का, वह भाव रेम्युनरेटिव हो, यह सब से बड़ा इन्सेंटिव है।

बोनस जो दिया जाता था प्रोक्यूरमेंट के ऊपर, वह भी किसान को सीधा नहीं पहुंचता था। वह स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता था और जो एजेन्सी उसकी प्रोक्यूरमेंट करती थी, और उस बोनस को इस्तेमाल किया जाता था किसान को सस्ता खाद और बीज वगैरह सप्लाई करने में।

श्री राम चन्द्र विकल : धान वाला जवाब तो रह गया, सभापति जी।

श्री सभापति : धान के लिए तो मिलता है बोनस।

श्री राम चन्द्र विकल : धान पर जो पांच रुपया बढ़ाया गया है, कृषि मंत्री जी ने कहा कि वह अगली फसल से बढ़ाया है, तो मैं चाहता हूं कि जो मौजूदा फसल है, इससे क्यों नहीं बढ़ाने की कृपा करते ?

राव बीरेन्द्र सिंह : पिछली फसल तो आ चुकी, किसान के पास है नहीं। अक्तूबर–नवम्बर से धान की फसल आनी शुरू होती है। अब उसको बढ़ा कर घर–घर कैसे पैसा पहुंचाया जाएगा। वह तो अगली फसल के लिए स्कीम मुकर्रर की गई है। पिछली प्रोक्यूरमेंट तो पिछले साल की मुकर्ररकर्दा कीमत के ऊपर हो चुकी।

श्री सभापति : यानी कि वह खा–पीकर खत्म हो गया सब मामला।

श्री इन्द्रदीप सिंह : सभापति महोदय, बोनस का अर्थ तो होता है डेफर्ज वेज ट्रेड यूनियंस में।

श्री सभापति : नहीं, नहीं यह ट्रेड यूनियन का सवाल नहीं है।

श्री इन्द्रदीप सिंह : वही, मैं सिद्धान्त पर सवाल उठा रहा हूं कि बोनस का अर्थ होता है डेफर्ड वेज। तो किसानों को गेहूं या चावल पर ऊपर बोनस दिया जाता है, तो उसका मतलब है कि जो प्राइस आपने फिक्स की है वह सारी कास्ट को या उनकी सारी वेजेज को कवर नहीं करता है और उनको बोनस देने की आवश्यकता है।

श्री सभापति : इस तरह से नहीं होता है।

श्री इन्द्रदीप सिंह : मैं जरा क्वेश्चन, फार्मुलेट कर लूं; तो उसके बाद जवाब दिया जाए।

तो अगर गवर्नमेंट इस प्रिंसिपल को मानती है कि सर्टेन क्राप्स की जो प्राइसज सरकार ने निर्धारित की है, वह सारी कास्ट का तथा जो मुनासिब मुनाफा मिलना चाहिए किसानों को, वह सब को कवर नहीं करता है, तो बोनस देने की आवश्यकता है।

तब तो इस एक आम सिद्धांत के तौर पर सरकार को स्वीकार करना चाहिए और यह फैसला नहीं करना चाहिए कि जब खुशी होगी तो किसी फसल में देंगे और किसी में नहीं देंगे। यह कोई सिद्धांत नहीं हुआ।

इसीलिए मैं सरकार से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि बोनस का जो अर्थ है ट्रेड यूनियन फील्ड में उसी अर्थ को मान कर के सरकार सभी फसलों के ऊपर बोनस देने के सिद्धांत को स्वीकार करे।

RAO BIRENDRA SINGH; Sir, I don't agree with the honourable Member that tx>"us is deferred wage, at least insofar as agriculture is concerned. Moreover, bonus, to my mind, means additional incentive ------

MR CHAIRMAN: It is like the sup. plementaries that I am allowing.

RAO BIRENDRA SINGH:....to the workers, to the producers, in addition to the normal prices or wages. Here, Sir, it is a question of price for the producers.

MR. CHAIRMAN; Yes. These two principles, Mr. Sinha, do not agree *and* thi$_s$ cannot toe inducted into agriculture.

SHRi INDRADEEP SINHA: Sir, the$_y$ also put in their labour; the peasants also put in their labour.

MR CHAIRMAN; That is right. But it cannot be applied here.

श्री नरेन्द्र सिंह : मान्यवर, कृषि, भारत का सबसे बड़ा उद्योग है, लेकिन भारत के किसानों को उद्योग में लगे हुए लोगों को जो सुविधाएं मिलती हैं, वह भारत के किसान को नहीं मिलती और उसे जो कीमत मिलनी चाहिए अपने उत्पादन की, वह भी नहीं मिलती है।

लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कृषि मंत्री जी या हमारी भारत सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि कृषि को भी उद्योग घोषित किया जाए, एक। दूसरा, इधर मान्यवर, कृषि उत्पादन की लागत बहुत बढ़ रही है, 5 रुपये तो प्रति क्विंटल बढ़ा दिया सरकार ने पैडी की कीमत लेकिन जो उत्पादन लागत है, जैसे मान्यवर, उत्तर प्रदेश में बिजली की कीमत ड्योढ़ी हो गई है 15 रुपये के बजाय साढ़े बाइस रुपये, बिजली का ड्योढ़ा रेट कर दिया है, लेकिन इसमें यह बढ़ोतरी हुई है सिर्फ 5 रुपये की तो मान्यवर क्या सरकार इस पर भी कुछ विचार करेगी कि किस प्रकार से उत्पादन लागत को कृषि के क्षेत्र में कम किया जा सकता है?

राव बीरेन्द्र सिंह : मान्यवर, जहां तक कृषि को इंडस्ट्री मानने के लिए विचार का सवाल है मैं समझता हूं, चेयरमैन साहब' अभी ऐसी तवज्जह सरकार के जेरेगौर नहीं है कि इसको इंडस्ट्री के तौर पर मांगा जाए।

श्री नरेन्द्र सिंह : यह सब से बड़ा उद्योग है।

राव बीरेन्द्र सिंह : माननीय सदस्य मैं मानता हूं कि यह सब से बड़ा उद्योग है' इसमें मैं आपके साथ सहमत हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह : क्या सरकार इस पर कुछ विचार करेगी कि इसको उद्योग घोषित किया जाए?

राव बीरेन्द्र सिंह : आपका सुझाव मैंने बड़े गौर से सुन लिया है और इस बात को मानने में मैं असमर्थ हूं कि किसान को काफी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं और उसको पूरी कीमत नहीं दी जा रही है। जो किसान के लिए कुछ चीजों की कीमत मुकर्रर की जाती है वह ए० पी० सी० की रिकमेंडेशन्स के ऊपर सरकार विचार करके तय करती हैं। वह कीमतें हमारी निगाह में रिमुनरेटिव हैं और उससे किसान को बहुत लाभ पहुंच रहा है। इसी वजह से कृषि के क्षेत्र के अन्दर पैदावार बढ़ रही है। हर साल हम कीमतों को रिवाइज करते हैं और सारी कास्ट जो बढ़ती जाती है उसको भी हम निगाह में रखते हैं। कोशिश यह भी रहती है कि किसान को जिन इनपुट्स की जरूरत होती है वह सस्ते दिए जाएं और आप यह भी जानते हैं कि कोऑपरेटिव सोसायटीज के जरिए से ज्यादा एग्रीकल्चर्स क्रेडिट मिलता है। उसका सूद का दर और बैंकों को कम है। इसी तरीके से हमने बहुत कोशिश की खाद का भाव घटाने की, खाद की कीमत से कम किया गया जिससे उसका खपत भी एकदम 40 परसेंट किसी-किसी स्टेट के अन्दर बढ़ गई। उसने पैदावार में भी बढ़ोतरी हुई। इसी तरीके से नहर का पानी है, बिजली है, किसान को सस्ती नहीं मिलती है, बिजली की दर भी हर स्टेट के अन्दर

कास्ट ग्राफ प्रोडक्शन से कम है ग्रौर उसके ऊपर भी स्टेट सरकार घाटा उठाती है ।

श्री नरेन्द्र सिंह : इन्डस्ट्री से ज्यादा है ? ·

राव बीरेन्द्र सिंह : वह इन्डस्ट्री से ज्यादा नही, वह -ग्रलग-ग्रलग स्टेट्स में ग्रलग-ग्रलग है, लेकिन जहां इन्डस्ट्री के लिए बढ़ जाती है .... (**व्यवधान**) उसी तरह पलेट रेट्स भी एग्रीकल्चर के लिए है बहुत सी स्टेट्स के ग्रन्दर जिन का दर काफी कम है । इसी तरह खाद के वितरण के ऊपर हर ब्लाक में सारे हिन्दुस्तान में चाहे वह स्थान रेल से दूर हो, चाहे रेल से नजदीक हो, पहाड़ों में हो या रेगिस्तान में हो, समुद्र पार हो एक ही कीमत पर खाद बेचा जाता है ग्रौर उससे ही 8 सौ से 1 हजार करोड रुपये का घाटा भारत सरकार उठाती है। तो ये चीजें है जिसके लिए ग्रापने हमारी तवज्जह दिलायी । ये इनीश्यिटिव दिए जा रहे हैं । इनपुट्स भी सस्ते दिए जा रहे हैं । इनपुट्स को वक्त पर पहुंचाने के लिए ठीक दाम पर देने के लिए, क्वालिटी ग्रच्छी करने के लिए, इनसैक्टीसाइड्ज, फटिलाइजर है, क्रेडिट पूरा पहुचाने के लिए, बीज ग्रच्छे देने के लिए, जो क्वालिटी सीड्ज की डिस्ट्रब्यूशन होती है ग्रौर प्रोडक्शन जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है 14 लाख क्विंटल बीज सन् 1980 के ग्रन्दर सर्टीफाइड तक्सीम किया गया ग्रौर ग्रब पिछले साल 57 लाख टन, चार गुने से भी ज्यादा सर्टीफाइड सीड की हमने क्वाटिटी बढ़ा दी इन चार वर्षों के ग्रन्दर ग्रौर ग्रागे हम इसको बहुत तेजी से पैदा कर रहे हैं, क्वालिटी सीड पैदा करके किसानों को पहुंचाने पर भी भारी घाटा भारत सरकार को उठाना पड़ रहा है। इसके ग्रन्दर भी सबसिडी है। तो बहुत सी चीजें सबसीडाइज्ड रेट के ग्रन्दर किसान को पहुंचा रहे हैं। तो यह बात माननीय सदस्य की गलत है कि किसानों को राहत पहुंचाने के लिए ग्रौर सस्ते इनपुट्स देने के लिए भारत सरकार काफी नहीं कर रही है ।

श्री नरेन्द्र सिंह : मैं यह नही कह रहा हूं कि नही कर रही है ग्रौर क्या प्रयास करेगी....... (**व्यवधान**) .

श्रीमती मैमूना सुल्तान : ग्रध्यक्ष महोदय, इसका गेहूं से बहुत हद तक ताल्लुक है । तो मैं यह पूछना चाहूंगी कि जहां तक मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया, इन्सेन्टिव दिए जा रहे हैं, यह बात तो सही है । लेकिन जो बोनस का कंसेप्ट है । यह मेरी समझ में नही ग्राता क्योंकि बोनस जो है, ग्राप दूसरे काश्तकारों को देते हैं, जिनकी पैदावार बढ़ी है, टारगेट ग्रापका बढ़ा है । जब पैदावार जिनकी पहले से ही ज्यादा है, उनको बोनस देने का क्या फायदा है । ग्रगर वही बोनस की रकम ग्राप छोटे किसानों को बढ़ा दें, तो उनको ज्यादा सहूलियत हो जाएगी ग्रौर ग्राप बोनस उन्ही को देते हैं, जो बड़े काश्तकार हैं। ग्रगर ग्राप इजाजत दें तो मैं एक वाक्या इस बारे सुना दू......

श्री सभापति : नहीं, नहीं । साल तो साफ है, व। से क्या होगा.....

राव बीर ह : जनाब, जो ग्रानरेबिल मेम्बर हैं, बात उनकी समझ में नहीं ग्राई, वह मेरी समझ में भी नही ग्राई बोनस की । हम बोनस नहीं दे रहे हैं ग्रौर बोनस देने के हक में नहीं हैं ।

श्रीमती मैमूना सुल्तान : ग्रगर ग्रापकी समझ में नहीं ग्राया, तो ग्र बोनस क्यों रखा है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : कहां रखा है, यही तो मैं भी कह रहा हूं कि बोनस नहीं दे रहे हैं और हम इसे नहीं मान रहे हैं।

श्री सभापति : यह दिलाना चाहते हैं, आप समझे नहीं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : सभापति जी, माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित पूछूंगा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि खाद के ऊपर 800 से एक हजार तीन सौ रुपए तक का सबसिडाइज कर रहे हैं और दे रहे हैं, तो क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि किसान का जिस भाव पर गेहूं खरिदते हैं और दूसरा अनाज खरीदा जाता है, कंज्यूमर को सबसिडाइज करने में कितना खर्च करते हैं, नम्बर एक और दूसरी बात जो उन्होंने बताया कि 57 लाख क्विंटल बीज उन्होंने सबसिडाइज करके किसानों को दिया, तो उसमें बताएंगे कि उसके रेट क्या है और सबसिडी लेकर के उसके क्या रेट हो गए ?

राव बीरेन्द्र सिंह : कोस्ट से काफी कम कीमत पर हम मुकर्रर करते हैं। लेकिन सवाल इस वक्त बीज का नहीं है, इसलिए मेरे पास पूरी इत्तला नहीं है। दूसरा फूड के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कितनी सबसिडी सरकार को बर्दाश्त करनी पड़ती है, यह सर, माननीय सदस्य को अगर आप कह दें कि यह फूड मिनिस्टर से संबंधित सवाल है।

MR. CHAIRMAN: Question No. 182.

*182. *[The* questioner *(Shri V.* Gopalsamy) toas absent.. For answer vide *cols.* 37-38 infra].

MR. CHAIRMAN. Question No. 183.

Allocation of Fertilisers to different States for tbe Kharif Season

*183. SHRI SURAJ PRASAD:!
SHRI INDRADEEP SINHA:

Will the Miinster of AGRICULTURE be pleased to state the details of the allocation of fertilisers to the different States for the kharif season during the current year?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA): A Statement indicating allocation of fertilisers made Statewise during the current Kharif 1984 season, is laid on the Table of the Sabha.

Statement

Allocation of Fertilisers made for Kharif, 1984 in nutrient terms

('000 tonnes)

	Name of State	Nitrogen	Phosphate	Potash
1	Andhra Pradesh	370·65	154·45	46·55
2	Karnataka	176·78	88·90	69·10
3	Kerala	39·45	19·20	21·00
4	Tamil Nadu	165·20	55·91	67·15
5	Gujarat	147·57	86·81	19·80
6	Madhya Pradesh	118·84	51 95	12·55

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Suraj Prasad.